Publication	**Navbharat Times**	**Language**	Hindi
Edition	New Delhi	**Journalist**	Murlidhar Mohol
Date	16/01/2025	**Page no**	10
CCM	59.57		

Cooperation is the guarantee of shared development for all

सबके साझा विकास की गारंटी है सहकारिता

मुरलीधर मोहोल

हाल ही नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ। इसमें सौ से अधिक देशों से नेताओं की आमद एक सतत एवं न्यायसंगत भविष्य को आकार देने में सहकारी समितियों के बढ़ते महत्व का प्रमाण है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया, जिसका मूल उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान आकर्षित कराना है।

सशक्त अध्याय | यह वर्ष वैश्विक, आर्थिक और सामाजिक विमर्श का वह महत्वपूर्ण अध्याय बन रहा है, जहां सहकारी समितियों को न केवल स्थानीय विकास के साधन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी पहचान दी जा रही है। भारत में सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उदाहरण के लिए, अमूल ने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, बल्कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक भी बन गया है।

भारतीय भूमिका | भारत ने लंबे समय से आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सहकारी समितियों के मूल्य को पहचाना है। नई दिल्ली में आयोजित ICA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर, समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने की सहकारी क्षेत्र की क्षमता पर भी प्रकाश डाला, खासकर ग्रामीण भारत में जहां सहकारी समितियां कृषि और डेयरी फार्मिंग जैसे क्षेत्रों की रीढ़ बनी हुई हैं। सरकार द्वारा सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम इस मान्यता को उजागर करते हैं कि सहकारी समितियां केवल अतीत

AI Image

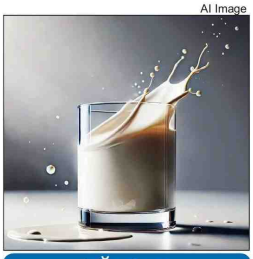

कॉमन रूम

की निशानी नहीं हैं, बल्कि समकालीन आर्थिक और सामाजिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

समस्याओं का हल | विश्व जब आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जूझ रहा है तो सहकारिता विकास के लिए एक समावेशी, लोकतांत्रिक और लचीला मॉडल पेश करती है। सहकारी मॉडल का जोर एकजुटता, आपसी सहयोग और लोकतांत्रिक भागीदारी पर है, जो इसे प्रमुख वैश्विक समस्याओं को संबोधित करने के लिहाज से अद्वितीय बनाता है। सहकारी समितियां वित्तीय लाभ से अधिक लोगों की प्राथमिकताओं पर जोर देती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों के लाभ और व्यापक रूप से वितरित हों। सहकारिता आंदोलन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर भारत ने खुद को सतत और समावेशी विकास के वैश्विक अधिवक्ता के रूप में स्थापित किया है।

आगे की राह | सहकारिता सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 'सहकार से समृद्धि' के विजन से ही 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश को एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जहां विकास को साझा किया जाता है और असमानताओं को कम किया जाता है।

(लेखक केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं)

****

Downloaded from
SAMVAD